

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 24, 1971/चैत्र 3, 1893

No. 44] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 24, 1971/CHAITRA 3, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

बजट 1971-72 वित्त मंत्री का भाषण 24 मार्च, 1971

महोदय,

मैं वर्ष 1971-72 का अन्तरिम बजट पेश करता हूँ। भारत की जनता ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, जो इस सम्मान्य सदन के सदस्य हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्ववाली सरकार में अपना असीम विश्वास प्रकट किया है। हम में से जिन व्यक्तियों को इस

सरकार का, और जिस दल की यह सरकार है उस दल का सदस्य होने का गौरव प्राप्त है, उन्हें यह भली भाँति मालूम है कि हम इस देश में जिस सीमा तक गरीब और बेरोजगार लोगों की भलाई करने के अपने वचनों को पूरा कर देंगे उसी सीमा तक हम जनता के इस निर्णय को न्यायोचित सिद्ध कर सकेंगे।

प्रस्तावना

2. सामाजिक न्याय के साथ विकास की ओर अग्रसर होने के उद्देश्य से अभी पिछले दिनों में, देश की आर्थिक नीतियों में नए और साहसपूर्ण परिवर्तन किए जा चुके हैं। अब हमारा कार्य यह है कि हम अपनी सम्पूर्ण नीतियों का फिर से मूल्यांकन करें ताकि हम उन नीतियों को ठोस कार्यक्रमों का रूप देने और तेजी तथा दृढ़ संकल्प के साथ उन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए उनकी प्रभावोत्पादकता को संकेन्द्रित कर सकें। केवल ऐसा करके ही हम विकास की गति को तेज कर सकेंगे, आय, सम्पत्ति और आर्थिक शक्तियों की असमान्यताओं को कम कर सकेंगे, विशाल पैमाने पर रोजगार पैदा कर सकेंगे और मूल्यों तथा शोषण-शेष (बैलेंस आफ पेमेण्ट्स) के उन दबावों को दूर कर सकेंगे जो आन्तरिक तनाव पैदा करते हैं और विदेशी ऋणों पर हमारी निर्भरता को बढ़ाते हैं।

3. केन्द्रीय सरकार का बजट हमारे बुनियादी उद्देश्यों को पूरा करने का एक सशक्त साधन है। नई सरकार जिन थोड़े दिनों से सत्तारूढ़ है, उनमें हमारी बजट सम्बन्धी स्थिति और नीतियों की सूक्ष्म और व्यापक समीक्षा करना सम्भव नहीं हुआ है, यह स्पष्ट ही है। अतः हम 1971-72 का मुख्य बजट संसद के आगामी सत्र में पेश करने का विचार करते हैं ताकि सरकार को और सम्मान्य सदस्यों को उन सभी विषयों की समीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए जो हमारे आर्थिक विकास की इस निर्णायक घड़ी में हम सबसे अपेक्षित हैं।

4. आज का मेरा उद्देश्य एक सीमित उद्देश्य अर्थात् लेखानुदान प्रस्तुत करना है जो 31 मार्च से पहले पास किया जाना है ताकि सरकार अगले वित्तीय वर्ष के पहले महीनों के दौरान, अपना काम चला सके। मैं आज बाद में जो वित्त विधेयक प्रस्ताव करूंगा, उसमें नए कर-प्रस्ताव नहीं हैं।

5. व्यय के खाते में, हमने रक्षा, सामान्य प्रशासन, राज्यों को सहायता और केन्द्रीय आयोजना के लिए उतनी ही व्यवस्था की है जितनी कि लेखानुदान की प्रारंभिक अवधि

मे सभी आवश्यक और उपयोगी गतिविधियों को चालू रखने के लिए जरूरी होगी। इस अवस्था में भी, देश भर में रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए जाने वाले उत्पादक निर्माण-कार्यक्रम जैसे कुछ नए और महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए व्यवस्था करने का प्रस्ताव करते हैं ताकि उनका कार्यान्वयन भली भाँति शुरू किया जा सके। आगामी मई मास में मुख्य बजट पेश करने से पहले विकास और सामाजिक कल्याण के परिचय (आउट-ले) में पर्याप्त वृद्धि के लिए व्यवस्था करने के उद्देश्य से, अधिक साधन जुटाने की गुंजाइश को भी ध्यान में रखते हुए, हम सम्पूर्ण स्थिति की समीक्षा करेंगे। अतः आयोजना-व्यय के अनुमान जो मैं आज प्रस्तुत करने वाला हूँ, अनन्तिम है। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि आयोजित विकास की गति वर्ष प्रति-वर्ष काफी तेज होती रहे।

आर्थिक स्थिति

6 पिछले बारह महीनों में देश की आर्थिक स्थिति, कुल मिलाकर अनुकूल रही है। आर्थिक स्थिति की विस्तृत समीक्षा ससद् के आगामी सत्र में प्रस्तुत की जाएगी। तथापि, सामान्य सदस्य मुझे देश की, पिछले वर्ष की अर्थव्यवस्था की मजबूती और कम-जोरियों की सक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करने की अनुमति देंगे।

7. यह लगातार दूसरा वर्ष है जब कि अर्थव्यवस्था के विकास की दर, कुल मिलाकर इतनी है कि उसे देखते हुए यह आशा की जा सकती है कि चतुर्थ आयोजना में निर्धारित लक्ष्यपूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएंगे। अनुमान है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय, जिसमें 1969-70 में लगभग 5.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, 1970-71 में भी उतनी ही और बढ़ जाएगी।

कृषि

8. अर्थव्यवस्था के समग्र विकास में कृषि के विकास का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अनाज का उत्पादन 1969-70 में 9.95 करोड़ मेट्रिक टन था और उसमें 5.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, आशा है, वह 1970-71 में 10.5 करोड़ मेट्रिक टन हो जाएगा और इस प्रकार उसमें फिर 5.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। आयात में उत्तरोत्तर कमी करते हुए भी, सरकार के पास अनाज का काफी बड़ा भंडार जमा हो गया है, जो इस समय 55 लाख मेट्रिक टन से भी अधिक का है, इसकी तुलना में एक वर्ष पहले यह भंडार 45 लाख मेट्रिक टन से कम का था। अधिक मात्रा में अनाज उपलब्ध हो जाने के फलस्वरूप अनाज के भावों में गिरावट आई है।

9. किन्तु, गन्ने को छोड़कर बाकी सभी वाणिज्यिक फसलों का, विशेष रूप से कपास और ते लहन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं हुआ है और औद्योगिक उत्पादन और मूल्यों पर इसका

प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। हमने ऋण और सट्टेबाजी की गतिविधियों पर रोक लगाकर और आयात में वृद्धि करके, कृषि संबंधी प्रमुख कच्ची सामग्री के मूल्यों में, अपर्याप्त उत्पादन के फलस्वरूप होने वाली वृद्धि को रोकने का प्रयत्न किया है। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने वाणिज्यिक फसलों की प्रति हैक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाने के लिए नए कार्यक्रम तैयार करने में कुछ सफलता प्राप्त की है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, मूल्यों को स्थिर करने और आयात पर कम निर्भर करने के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि बारानी इलाकों में हमारे अधिकांश गरीब किसानों के रहन-सहन को सुधारने के लिए भी जरूरी है। मैं सम्मान्य सदस्यों को यह आश्वासन देता हूँ कि वाणिज्यिक फसलों की प्रति हैक्टेयर उपज को बढ़ाने के लिए जो भी आशाजनक कार्यक्रम तैयार किये जायेंगे उनके लिए हम वित्तीय और अन्य प्रकार की अधिक से अधिक सहायता देंगे।

उद्योग

10. वर्ष के दौरान औद्योगिक उत्पादन में, कुल मिलाकर, लगभग 6 प्रतिशत की वृद्धि होने की आशा है। औद्योगिक उत्पादन में जो बढ़ोत्तरी हुई है वह केवल पूंजीगत माल तैयार करने वाले उद्योगों, विशेष रूप से मशीनें और मशीनी औजार बनाने वाले उद्योगों ने ही नहीं की है, अपितु इसमें, महत्वपूर्ण मध्यवर्ती माल तैयार करने वाले उद्योगों, जैसे एल्यूमीनियम, नाइट्रोजनी उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद और भारी रसायन उद्योगों ने तथा अनेक प्रकार के उपभोक्ता-वस्तु उद्योगों ने भी अपना योगदान दिया है। नए उद्योगों और लघु उद्योगों का काम भी उत्साहवर्धक रहा है। तथापि, अब भी नथ्य यही है कि देश में औद्योगिक उत्पादन की गति काफी तेज करने की जरूरत है, और इसी उद्देश्य से कृषि संबंधी और औद्योगिक दोनों ही प्रकार की कच्ची सामग्री, विशेष रूप से इस्पात, की पूर्ति को जल्दी से जल्दी बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य को सामाने रखने हुए, सरकार बोकारो इस्पात कारखाने को जल्दी से जल्दी पूरा करने, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के मौजदा इस्पात कारखानों के उत्पादन को बढ़ाने और वक्षिण के राज्यों में तीन नए इस्पात कारखाने स्थापित करने का विचार कर रही है। इन नए इस्पात कारखानों का प्रारंभिक कार्य संतोषजनक रूप से आगे बढ़ रहा है। यहां भी हम वित्तीय तंगी के कारण, उनकी प्रगति को किसी प्रकार कम न होने देंगे।

11. 1970 के दौरान अनुमोदित किए गए, नए औद्योगिक पूंजीनिवेश के प्रस्ताव, पिछले वर्ष की इसी अवधि के प्रस्तावों से परिमाण की दृष्टि से, काफी बड़े थे। देश में पूंजीगत माल का उत्पादन बढ़ रहा है और तदनुसार पूंजीगत माल के आयात के लिए आवेदन-पत्रों की संख्या भी बढ़ रही है। हम औद्योगिक पूंजीनिवेश की इस प्रक्रिया को तीव्र गति देने के लिए प्रयत्न करेंगे ताकि रोजगार के अधिक अवसर पैदा हों और आने वाले वर्षों में बुनियादी वस्तुओं की कोई कमी न रहे।

12. सम्मान्य सदस्यों को विदित हो है कि गत वर्ष हमने औद्योगिक लाइसेंस देने, एकाधिकारों पर नियंत्रण रखने और सरकारी वित्तीय संस्थाओं की नीतियों में, पिछड़े प्रदेशों तथा नए उद्यमकर्ताओं को सहायता देने एवं राष्ट्रीय हित की दृष्टि से सहायता प्राप्त करने वाले बड़े एककों के प्रबन्ध और लाभकारिता में हिंसा बंटाने पर अधिक जोर देने के उद्देश्य से, अनेक महत्वपूर्ण नीति-विषयक निर्णय लिये थे। आगे और औद्योगिक विकास करने की विरुल सम्भाव्य शक्ति को, जो कि हमने अपने पिछले बीस वर्षों के प्रयत्नों से उत्पन्न की है, हम तब तक पूरी तरह उपयोग में नहीं ला सकेंगे जब तक कि छोटे लोगों को अधिक संख्या में, नए कार्यक्षेत्रों और उद्योग-धन्धों के कार्यक्षेत्र में न लाया जाएगा। अर्थव्यवस्था के समग्र हितों की दृष्टि से, बड़ी मात्रा में नए पूँजी-निवेश करना या मौजूदा बड़े एककों का विस्तार करना जब जरूरी हो जाएगा, उस समय हमारा यह प्रयत्न होगा कि संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना के कल्पनाशील और लचीले उपयोग द्वारा और सरकारी क्षेत्र का विस्तार करके आर्थिक शक्ति के कुछ हाथों में जमाव को कम करने की प्रक्रिया के साथ विकास और कार्यकुशलता का सामंजस्य स्थापित किया जाए।

मूल्य-स्थिति

13. 1970 के उत्तरार्द्ध में, देश में मूल्य-स्थिति चिन्ता का विषय बन गई थी क्योंकि थोक-मूल्य-सूचकांक लगातार कई सप्ताहों तक, पिछले वर्ष के उन्हीं सप्ताहों का तुलना में, 7 प्रतिशत या इससे भी अधिक ऊँचा रहा था। हाल के सप्ताहों में सामान्य-मूल्य-सूचकांक, 1970 के इन्हीं सप्ताहों के सूचकांक की तुलना में, 4 प्रतिशत या इससे कम की वृद्धि सूचित करता है। फिर भी, मूल्य-स्थिति को देखते हुए लगातार सतर्क रहने की आवश्यकता है और हम सर्वसाधारण के काम में आने वाली अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में उचित अंश तक स्थिरता लाने के लिए शक्तिशाली कदम उठाने का विचार करते हैं।

14. मूल्यों में जो वृद्धि हो रही है, वह समस्त विश्व में चिन्ता का विषय बनी हुई है और शायद ही ऐसा कोई देश हो जो इन हाल के वर्षों में प्रतिवर्ष 3 से 4 प्रतिशत तक की न्यूनतम सामान्य मूल्य वृद्धि का रोकन में सफल हुआ हो। तथापि हम लगातार हो रही इस मूल्य वृद्धि के परिणामों को, विशेष रूप से बंधी आय वाले वर्गों और गरीब लोगों के रहन सहन के स्तर पर पड़ने वाले उसके प्रभावों को नजरंदाज नहीं कर सकते। अब यह बात सब जगह सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है कि जब तक बेतन और मूल्यों को और इनके जरिये आय को नियंत्रित करने की सक्रिय नीति नहीं अपनाई जाती, तब तक हम एक के बाद दूसरे उद्योग में लगातार बढ़ते हुए मूल्यों पर काबू नहीं पा सकते। हमारी परिस्थितियों में, मूल्य वृद्धि का एक बड़ा कारण बुनियादी कच्ची सामग्री की कमी भी है, जिससे हम केवल कुछ सीमा तक अधिक आयात करके ही पूरा कर सकते हैं। अतः बुनियादी वस्तुओं के उत्पादन की वृद्धि करने के प्रयत्न करना ही किसी भी मूल्य-नीति का एक अत्यावश्यक अंग है। सट्टेबाजी के द्वारा, कुछ समय के लिए अप्रतिहार्य रूप से हो जाने वाली कमियों को बढ़ाने-चढ़ाने की हर कोशिश को भी मजबूती से दबा देना होगा।

15. उत्सादन में हुई वृद्धि को देखते हुए मुद्रा उपलब्धि में जिनकी वृद्धि होनी चाहिए थी उससे अधिक वृद्धि हुई है। केन्द्रीय सरकार के बजट का घाटा उतना ही रहा है जितना हमने पिछले बजट में दिखाया था। तथापि, चालू वर्ष के अधिकांश दिनों में रिजर्व बैंक से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधार ली गई राशि का स्तर असामान्य रूप से ऊंचा रहा है। इसी पृष्ठभूमि को आधार बनाकर रिजर्व बैंक ने जनवरी मास के पहले दिनों में बैंक दर को 5 प्रतिशत से बढ़ा कर 6 प्रतिशत कर दिया है और साथ ही, उसने बचतों के लिए प्रोत्साहन देने और जमा की रकमों जुटाने में सहायता देने के लिए तथा प्राथमिकता-प्राप्त प्रयोजनों को छोड़ कर अन्य प्रयोजनों के लिए अपने यहां से (रिजर्व बैंक से) उधार राशि लेने में बैंकों को निरुत्साहित करने के उद्देश्य से बहुत से उपाय किए हैं। इन उपायों का और इनके साथ ही, कम मात्रा में उपलब्ध होने वाली वस्तुओं के लिए अधिमां पर चयनात्मक नियंत्रणों को कड़ा करने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है।

चितीय संस्थाएं

16. सम्मान्य सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि देश में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का महत्वपूर्ण कदम उठाते समय हमने जो उद्देश्य अपने सामने रखे थे उनकी प्राप्ति की दिशा में शानदार गुरुप्राप्त हो चुकी है। उदाहरणार्थ राष्ट्रीयकरण के बाद के पहले सत्रह या अठारह महीनों में, यानी 19 जुलाई, 1969 से 31 दिसंबर, 1970 तक की अवधि में सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने, यानी चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों ने और भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सात सहायक बैंकों ने प्रतिमास औसतन 145 नई शाखाएं खोली हैं, जबकि उन्होंने 1969 की पहली छमाही में प्रतिमास 80 और 1968 में प्रतिमास 47 शाखाएं खोली थीं। नई शाखाओं में से लगभग 70 प्रतिशत शाखाएं उन स्थानों पर खोली गई हैं जहां पहले बैंकिंग सुविधाएं बिल्कुल नहीं थीं, और इन शाखाओं में से भी अधिकांश शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में खोली गई हैं। देश को 330 से अधिक जिलों में बैंकिंग सुविधा का गहन विकास करने के लिए अपनाई गई 'बैंक नेतृत्व योजना' (लीड बैंक स्कीम) के कार्यान्वयन में संतोषजनक प्रगति हो रही है। लगभग 80 जिलों के सर्वेक्षण की रिपोर्टें तैयार हो चुकी हैं और दूसरी कई रिपोर्टें तैयार होने वाली हैं। इन सर्वेक्षणों से निकाले गए परिणामों को संकलित किया जा रहा है और नई शाखाएं खोलने के लिए वाणिज्यिक बैंकों को केन्द्र सौंपने का काम लगातार चल रहा है। नई शाखाओं ने स्थानीय जमा की रकमों को जुटाने और उनका उन्हीं क्षेत्रों में उपयोग करने का जो काम किया है वह विशेष रूप से सराहनीय है।

17. समाज के जो अपेक्षाकृत कमजोर वर्ग अब तक ऋण दिए जाने के मामले में बैंकों द्वारा उपेक्षित रखे गए थे, उन पर भी अब विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पहले जो क्षेत्र उपेक्षित रहे थे, जैसे कृषि, लघु-उद्योग, सबक परिवहन चालक, छोटे व्यापारी और आत्मनियोजित (सैल्फ एम्प्लाइड) व्यक्ति और पेशेवर लोग, उनके उधारखातों की कुल संख्या, जो जून 1969 के प्रारम्भ में 3 लाख से कुछ कम थी, नवम्बर 1970 के अन्त तक बढ़कर 11 लाख से भी अधिक हो गई और इन क्षेत्रों की कुल सहायता लगभग दुगुनी हो गई। इस वर्ष के प्रारम्भिक दिनों में भारतीय ऋण प्रत्याभूति निगम की स्थापना की

गई है। इसने अग्रतः उद्दिष्ट रहे क्षेत्रों को ऋण देने की प्रक्रिया में और भी तेजी आ जाएगी। जब भिन्न भिन्न ऋण दरों को योजना लागू हो जाएगी तो छोटे ऋणकर्ताओं को भी लाभ मिल सकेगा; इस समय एक समिति इस योजना के व्योरे तैयार कर रही है।]

18. सम्मान्य सदस्य यह महसूस करेंगे कि अन्य उत्पादक प्रतिष्ठानों की वास्तविक आवश्यकताओं की उपेक्षा न करते हुए, समाज के कमजोर वर्गों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने की, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की क्षमता अन्ततोगत्वा इस बात पर निर्भर करेगी कि वे जमा की रकमों जुटाने में कितनी सफलता प्राप्त करते हैं और सब प्रकार के अपव्ययपूर्ण और अनुत्पादक ऋण देने से बचने के लिए ऋणों के अन्ततः उद्दिष्ट उपयोग की जाँच पड़ताल करने की कितनी योग्यता रखते हैं। हालाँकि इन दोनों ही उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों ने अच्छी शुरुआत की है, फिर भी मैं यह भली भाँति समझता हूँ कि इन विषय में और ग्राहकों को पहले से अच्छी सेवा प्रदान करने की दिशा में अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। हमारा विचार है कि कर्मचारियों को सार्थक प्रशिक्षण देने की मुविधाओं को बहुत अधिक बढ़ाया जाए और कार्मिक नीतियों को भी नया रूप दिया जाए ताकि सभी स्तरों पर कर्मचारियों और प्रबंधकों में अधिक सौहार्द और समर्पण की भावना जागृत हो। बैंक कर्मचारी स्वयं भी अनेक वर्गों से बैंक राष्ट्रीयकरण के सबसे कटुतर समर्थक रहे हैं और हमने भी, अपनी ओर से, उनके वेतन-भत्तों और उनकी काम करने की स्थितियों में सुधार करने की उचित माँगों पर ध्यान देने में कोई ढील नहीं की है। मुझे आशा और विश्वास है कि बैंक कर्मचारी, अलग, अलग और सामूहिक रूप से भी, देश के आर्थिक कार्याकल्प के महत्वपूर्ण कार्य में अपना पूरा योगदान देंगे।

19. लम्बी अवधि के लिए वित्त व्यवस्था करने वाली संस्थाओं जैसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, औद्योगिक वित्त निगम और जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट के लिए यह वर्ष भी सफलता पूर्ण रहा है। सम्मान्य सदस्यों को सम्भवतः विदित ही है कि औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम नामक एक नया निगम स्थापित किया जा रहा है जिसका मुख्यालय कलकत्ता में होगा। आशा की जाती है कि यह निगम विशेष रूप से पूर्वी अंचल में कलकत्ता और उसके चारों ओर के इलाकों में अपना महत्वपूर्ण कार्य करके दिखाएगा। जहाँ संभव होगा यह निगम ऐसे औद्योगिक एककों को, जो अभी हाल ही में बन्द हो गए हैं या बन्द हो जाने का खतरा झेल रहे हैं, जेवर पूँजी का पुनर्निर्माण करके, प्रबन्ध मजबूत करके, उत्पादों में विविधता लाकर, प्रौद्योगिकी और श्रमिक सम्बन्धों में सुधार करके और समुचित रूप से उदार शर्तों पर वित्त-व्यावस्था करके, उन्हें फिर से अच्छी तरह चलाने का प्रयत्न करेगा। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि सब सम्बन्धित पक्षों के योगदान और सहयोग से, यह निगम बेरोजगारी को और अर्थ-व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में व्याप्त आर्थिक सामाजिक तनावों को कम करने के कार्य में अपनी उपयोगी भूमिका अदा करेगा।

शोधन-दोष

20. सम्मान्य सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि चालू राजस्व वर्ष के अंत तक हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि को वे सब बकाया रकमें चुका दी थीं जो हमें 1966 और 1967 के नाजुक

वर्षों में उससे लेनी पड़ी थी। इसके अतिरिक्त हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के अपने ग्रंथ (कोटे) में 75 करोड़ डालर से 94 करोड़ डालर की वृद्धि से संबंधित अपने धायित्वों को भी पूरा कर लिया है। हम विशेष आहरण अधिकारों (स्पेशल ड्राइंग राइट्स) की योजना के भी प्रमुख लाभानुभागी रहे हैं।

21. हालांकि पिछले दो-तीन वर्षों में हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति में कुल मिलाकर सुस्पष्ट सुधार हुआ है, फिर भी मैं इस बात पर जोर दिए बिना नहीं रह सकता कि हमारे शोधन-शेष (बैलस ऑफ पेमेंट्स) में किसी प्रकार का आत्म-संतोष कर लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। उदाहरणार्थ, चालू वर्ष के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि के संबंध में हमारी स्थिति में जितना सुधार हुआ है वह विशेष आहरण अधिकारों सहित हमारी अपनी संचित निधि में उतनी ही कमी हो जाने से बराबर हो जाएगा जिससे कि संतुलन करने पर, हमारी कुल संचित निधि की स्थिति में सुधार बहुत थोड़ा या बिलकुल नहीं दिखाई देगा। अर्थ-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जारी किए गए आयात लाइसेंसों में भी काफी वृद्धि हुई है। उसका सम्पूर्ण असर तो अभी महसूस करना है। निर्यात की आय में प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत वृद्धि करने का जो लक्ष्य चतुर्थ आयोजना में निर्धारित किया गया है, उसे यदि वर्ष प्रति वर्ष प्राप्त करना है तो हमें व्यापक क्षेत्र में लगाना और भी अधिक प्रयत्न करने होंगे। विदेशी सहायता की शुद्ध (नेट) प्राप्ति की संभावना अनिश्चित बनी हुई है। यह स्थिति, विशेष रूप से तत्काल उपयोग में लायी जा सकने वाली सहायता जैसे, आयोजना भिन्न सहायता और हमारे भारी ऋणों के परिशोधन के लिए पुनर्वित्त-व्यवस्था के सम्बन्ध में बनी हुई है।

22. ऐसी स्थिति में, हमारे लिए यही बुद्धिमतापूर्ण होगा कि हम निर्यात की वृद्धि और आयात के प्रतिस्थापन (इम्पोर्ट सबस्टीट्यूशन) के प्रत्येक सुअवसर का लाभ उठाएं और कम आवश्यक वस्तुओं के उपभोग और आयात पर अधिक से अधिक नियंत्रण रखें। इससे एकबार फिर, लागतों और मूल्यों पर काबू पाने की और उपभोग को विनियमित करने के लिए कर-साधनों का उपयोग करने की आवश्यकता पर जोर देने की जरूरत महसूस होती है। पूंजी-निवेश की प्राथमिकताओं का निर्धारण भी शोधन-शेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करना होगा। हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि हमारा उद्देश्य, न केवल सामाजिक न्याय के साथ अपितु आत्मनिर्भरता के साथ भी, विकास को और अग्रसर होता है। इनमें किसी एक मोर्चे पर भी सफलता प्राप्त करके संतोष की सांस लेने से पहले, हमें बहुत लम्बी मंजिल तय करनी पड़गी।

रोजगार

23. इस समय सबसे पहले हमें जिस विकट समस्या की ओर पूरे दिल से ध्यान देने की जरूरत है वह है बेरोजगारी की समस्या। यही वह समस्या है जो हमारे अल्पवयस्क लोकतन्त्र के स्थायित्व के लिए सबसे अधिक खतरे वाली बात बनी हुई है। इस बात के संकेत तो मिलते हैं कि पिछले दो वर्षों में कृषि सम्बन्धी और औद्योगिक उत्पादन के पुनरुत्थान के फलस्वरूप देश में रोजगार भी स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। परन्तु तथ्य यही रहा है कि पिछले दो दशकों में हमारी तेज आर्थिक प्रगति के बावजूद भी

जन-सामान्य की गरीबी और बेरोजगारी की दोनों जुड़वां समस्याएँ उतनी ही विकट बनी हुई हैं जितनी कि पहले कभी थीं। बड़े अंचलों में तो हालत शायद पहले से भी अधिक खराब हो गई है। इस बात को तो बिल्कुल नहीं झुठलाया जा सकता कि गरीबी और बेरोजगारी का उन्मूलन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि विकास की प्रक्रिया को निरन्तर जारी नहीं रखा जाता। परन्तु विकास करने के भी अनेक तरीके होते हैं हमें और उन तरीकों को खोज निकालना है जिनसे जन-साधारण की बेरोजगारी की समस्या अधिक से अधिक सुलझ सके।

24. इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ समय पहले यह निर्णय लिया था कि देश के प्रत्येक जिले में रोजगार दिलाने वाली योजनाएं चालू की जाएं जिससे कि प्रत्येक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को तो रोजगार मिल सके। इस बारे में राज्य सरकारों को भी ये निर्देश दिये जा चुके हैं कि वे भी ऐसी योजनाएं तैयार करें जिनमें रोजगार के अधिक अवसर तो सुलभ हों ही, साथ ही प्रत्येक जिले की उत्पादन क्षमता में भी वृद्धि हो। उत्पादन वृद्धि के साथ साथ अधिक रोजगार के अवसर सुलभ करने के देश-व्यापी कार्यक्रम के लिए 1971-72 के बजट में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है।

25. भारतीय रिजर्व बैंक ने बाणिज्यिक बैंकों की विशेष ऋण योजनाओं की समीक्षा करने के लिए जो समिति बनाई थी उसने आत्मनियोजन (सेल्फ एम्प्लायमेंट) को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए कई बहुमूल्य सुझाव दिये हैं। समिति ने जो सिफारिशें की हैं उन पर तत्परता से विचार किया जा रहा है और उसके सम्बन्ध में निर्णय शीघ्र ही लिये जायेंगे।

1970-71 के बजट का प्रतिफल

26. गत वर्ष प्रधान मंत्रिमहोदया ने जो बजट प्रस्तुत किया था उसमें केन्द्र स्तर पर आयोजना परिषद में पर्याप्त वृद्धि करने तथा राज्य स्तर पर आयोजना-परिव्यय में ऐसी ही वृद्धि करने के लिए राज्यों को भारी सहायता देने और समाज के मध्य से अधिक जहरतमन्द वर्गों के कल्याण के लिए अधिक तत्परता के साथ विकास की ओर अग्रसर होने के कई नए कार्यक्रमों की शृंखला के लिए धन की व्यवस्था की गई थी। इस वर्ष के दौरान, हमने राज्यों को दिए गए अपने वचनों को पूरा कर दिया है, और उनके बजट में की गई व्यवस्था के अलावा भी उन की तत्कालिक आवश्यकताओं के लिए, जैसे कलकत्ता के महानगरीय क्षेत्रों में रहन-सहन की स्थिति में सुधार करने के लिए और अन्य राज्यों के बाढ़ तथा अकालग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए वस्तुतः काफी सहायता प्रदान की गई है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन और परिवार पेंशन में भी वृद्धि की जा चुकी है। कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की सूरत में एक मुश्त रकम प्रदान करने की और परिवार पेंशन देने की ऐसी ही एक योजना उन औद्योगिक कर्मचारियों के लिए पहले ही लागू की जा चुकी है जिन्हें अपने वेतन का $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत भाग कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान करना पड़ता है और जो कोयला खान भविष्य निधि और बोनस योजना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत आते हैं। अभी हाल ही में स्थापित किए गए आवास और नगर विकास वित्त निगम ने अपने कार्यकलापों का श्रीगणेश कर दिया है और यह मुनिश्चित करना हमारा प्रयत्न होगा कि ये कार्यकलाप तेज गति पर चले जाएं ताकि हमारे बड़े बड़े नगरों

में कुछ ठोस सुधार हो सके। आदिम जातीय क्षेत्रों और गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के पोषण के कार्यक्रम पीने का पानी मुलभ करने की योजनाएं, और छोटे किमानों, सीमान्तिक (मार्जिनल) किमानों तथा बोरानी खेती के इलाकों के लिए विशेष योजनाएं चालू की जा चुकी हैं। बहुधा सुखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों में कुछ चुने हुए ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों पर सम्भवतः 25 करोड़ रुपये के निर्धारित लक्ष्य से कम खर्च होगा क्योंकि समयोचित योजनाएं बनाने और उनको अन्तिम रूप देने में समय लग गया था; फिर भी, सम्मान्य सदस्यों को कृपया ज्ञात रहे कि प्राकृतिक विपत्तियों में राहत देने के लिए, इस व्यवस्था के बाहर, 100 करोड़ रुपये की और राशि प्रदान की गई थी जिसके लिए बजट में केवल 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। इन विशेष योजनाओं को आगे भी चालू रखने के लिए आगामी वर्ष के बजट में व्यवस्था की जा रही है।

27. यह विश्वास करना पूर्णरूप से युक्तियुक्त होगा कि चालू वर्ष में राज्य स्तर पर आयोजना-परिचय में वृद्धि करने की जो कल्पना की गई थी वह पूरी हो जाएगी और कई राज्यों में तो आयोजना-परिचय प्रारम्भिक व्यवस्था से भी अधिक हो जाएगा। कमजोर वित्तीय स्थिति वाले राज्यों को विशेष सहायता देने के लिए बजट में 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, उसे बढ़ाकर 195 करोड़ रुपये कर दिया गया है और उसके लिए संशोधित अनुमानों में व्यवस्था की जा रही है। फिर भी, यह चिन्ता का विषय है कि विशेष सुविधाओं के लिए पहले से अधिक व्यवस्था करने के बावजूद भी, कुछ राज्य सरकारें भारतीय रिजर्व बैंक से भारी ओवर-ड्राफ्ट लेती रही है और इस प्रकार अर्थ-व्यवस्था में मुद्रास्फीतिकारी दबाव बढ़ाती रही हैं। विशेष सुविधा के लिए निर्धारित राशियां आगे आने वाले वर्षों में, सम्मत पद्धति के अनुसार, कम होनी चली जाएंगी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यह बहुत ही जरूरी हो गया है कि राज्य सरकारें, राजस्व के मामले में कड़ा अनुशासन बरतने और साधन जुटाने तथा उन्हें जमा रखने के सभी सम्भव उपाय करने में केन्द्रीय सरकार से किसी प्रकार भी पीछे न रहे।

28. जहां तक केन्द्र स्तर पर आयोजना-परिचय का सम्बन्ध है, ऐसे संकेत मिले हैं कि 1970-71 का वास्तविक व्यय, 1969-70 के वास्तविक व्यय की तुलना में, काफी, यानी 180 करोड़ रुपये, अधिक होगा। किन्तु यह देखकर बहुत निराशा होती है कि दोनों ही वर्षों में वास्तविक-परिचय, मूल बजट व्यवस्था की तुलना में, सम्भवतः काफी कम होगा। केन्द्रीय क्षेत्र की बहुत-सी औद्योगिक आयोजनाएं, विशेषतः बोकारों इस्पात कारखाना, उर्वरक संयंत्र और पेट्रो-रसायन आयोजनाएं उतनी तेजी से प्रगति नहीं कर सकी हैं जैसी कि आशा थी। स्पष्ट है कि हमें आयोजना की बड़ी-बड़ी योजनाओं की छान बीन करने और उनके लिए स्वीकृति देने की वर्तमान प्रक्रियाओं की विवेचनात्मक जांच करने और उनके कार्यान्वयन में अधिक मति लाने की आवश्यकता है। केन्द्रीय आयोजना में सम्मिलित बड़ी-बड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने का हमारा इरादा है ताकि आने वाले वर्ष में उनके लिए की जाने वाली व्यवस्था यथासम्भव यथार्थतापूर्ण हो। आवश्यकता की कमियों को पूरा करने के लिए कुछ ऐसी अतिरिक्त योजनाएं भी तैयार रखी जाएंगी जो तत्काल चालू की जा सकती हों और जो जल्दी से प्रतिफल दे सकती हों और साथ ही गरीब लोगों की भलाई के लिए भी कुछ कर सकती हों। मैं सम्मान्य सदस्यों को यह बात बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यद्यपि आयोजना सम्बन्धी प्राथमिकताओं में फिर से कुछ समायोजन

करने और आयोजनागत कार्यक्रमों का फिर से क्रम-निर्धारण करने की आवश्यकता तो अवश्य है, किन्तु आयोजना के आकार को छोटा करने का कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता; बल्कि हमारा इरादा तो इसे बढ़ाने का है।

29. चालू वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमानों में, कर-राजस्व, विशेषरूप से आय और निगम कर संप्राप्त होने वाले राजस्व, 1970-71 के बजट अनुमानों की तुलना में कुछ अधिक, होंगे, ऐसी आशा है। इस प्रकार चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में कर-राजस्व 3,198 करोड़ रुपये दिखाया गया है जबकि बजट अनुमानों में वह 3,134 करोड़ रुपये रखा गया था। कर-भिन्न राजस्व में भी इसी प्रकार की वृद्धि होने की सम्भावना है। किन्तु, राजस्व प्राप्तियों में यह जो वृद्धि हुई है, वह बाजार ऋणों के अन्तर्गत लगभग 26 करोड़ रुपये और विदेशी सहायता के अन्तर्गत लगभग 50 करोड़ रुपये की कमी हो जाने से प्रतिसंतुलित हो जाएगी। आयोजना पर चालू वर्ष में हुए व्यय और राज्यों को दी गई सहायता के रूप में हुए व्यय की स्थिति के बारे में, मैं पहले ही संक्षेप में बता चुका हूँ। आयोजना-भिन्न व्यय के खाते में अन्तर डालने वाली बड़ी मद थी—वेतन आयोग का अन्तरिम पंचाट (एवार्ड), जो कि सरकार द्वारा पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया था। कुल मिलाकर, और आंशिक रूप से वेतन आयोग के अन्तरिम पंचाट के फल-स्वरूप सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का बजट में योगदान पहले से कम होने की उम्मीद है। इनमें से कुछ उद्यमों को उनकी तकद हानि और कार्यचालन खर्च को पूरा करने के लिए दिए जाने वाले ऋणों की राशि भी, बजट में की गई व्यवस्था की तुलना में, कोई 30 करोड़ रुपये अधिक होगी। संतुलन करने पर, केन्द्र सरकार के चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में अब 230 करोड़ रुपये का बजट सम्बन्धी घाटा रहने का अनुमान है, जो बजट अनुमानों में दिखाए गए 227 करोड़ रुपये के घाटे के लगभग बराबर ही बैठता है।

बजट अनुमान 1971-72

30. करों की वर्तमान दरों के अनुसार, अगले वर्ष कुल 3,403 करोड़ रुपये का कर-राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है, जिसमें से 850 करोड़ रुपया राज्यों के हिस्से में आएगा। आशा है, कर-भिन्न राजस्व, जिसमें खाद्य सहायता और पी० एल० 480 के राजस्व-अनदान शामिल नहीं हैं, बढ़कर अगले वर्ष 966 करोड़ रुपये हो जाएगा जबकि वह इस वर्ष 908 करोड़ रुपए था। बाजार-ऋणों और अल्प बचतों की प्राप्तियों में, बढ़ोतरी होगी, परन्तु विदेशी सहायता की प्राप्तियों में काफी कमी हो जाने अर्थात् इस वर्ष के 518 करोड़ रुपये से घटकर 1971-72 में 421 करोड़ रुपये रह जाने की सम्भावना है। इसमें से अधिकांश कमी पी० एल० 480 की प्राप्तियों के अंतर्गत होगी। प्रयोग आयोजना-भिन्न और आयोजनागत सहायता की शुद्ध प्राप्तियों में भी कमी हो जाने की सम्भावना है और अनुमान है कि वे इस वर्ष के संशोधित अनुमानों में दी गई 355 करोड़ रुपये की राशि से घटकर अगले वर्ष 324 करोड़ रुपये रह जाएंगी।

31. व्यय खाते में, सामान्य प्रशासनिक व्यय, चालू वर्ष की तुलना में, 15 करोड़ रुपये अधिक होगा। रक्षा व्यय के राजस्व और पूंजी दोनों खातों में, चालू वर्ष की बजट व्यवस्था की तुलना में, 65 करोड़ रुपये

की अनिश्चित व्यवस्था की जा रही है। मैंने जिन राजगार दिलाने वाली योजनाओं का पहले उल्लेख किया है उनके लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था को फिलहाल आयोजना से बाहर माना जा रहा है। इसको छोड़कर, 1971-72 की आयोजना के लिए केन्द्रीय बजट में 1980 करोड़ रुपये की व्यवस्था होगी, यह राशि चालू वर्ष के बजट अनुमानों से 74 करोड़ रुपये अधिक है। यह सारी वृद्धि राज्य सरकारों और संघीय राज्य क्षेत्रों को दी जाने वाली आयोजना सम्बन्धी सहायता के कारण हुई है जिसके लिए इस वर्ष 711 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी, जिसे बढ़ाकर अगले वर्ष 785 करोड़ रुपये किया जा रहा है। यह वृद्धि, योजना आयोग और राज्य सरकारों के बीच, उनकी 1971-72 की आयोजनाओं के सम्बन्ध में किए गए विचार-विमर्श के आधार पर की गई है। मैंने इस अवस्था में भी, राज्यों को आयोजना सहायता देने के लिए पूरी व्यवस्था करना चाहा है ताकि राज्य सरकारें, अगले मई मास में प्रस्तुत किए जाने वाले केन्द्रीय बजट की प्रतीक्षा किए बिना ही, अपनी 1971-72 की वार्षिक आयोजनाओं को आगे चलाती रहे।

32. अगले वर्ष, केन्द्रीय सरकार की मुख्य आयोजना के लिए 1,195 करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की गई है वह उतनी है जितनी कि चालू वर्ष के बजट में की गई थी, हालांकि संभावित व्यय को देखते हुए जो अन्तर्निर्मित व्यवस्था अब कि जा रही वह काफी अधिक होगी मैं यह पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ कि हम मई मास में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट में, केन्द्रीय आयोजना सम्बन्धी व्यवस्था को बढ़ाना चाहेंगे और यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयत्न करेंगे कि मुख्य केन्द्रीय आयोजना के विभिन्न कार्य क्रमों के परिव्यय के लिए की जाने वाली व्यवस्थाओं की छानबीन और उनका फिर से क्रम-निर्धारण इस प्रकार किया जाए कि वे सब कमियाँ दूर हो जाएं जिन्होंने पिछले दो वर्षों में परेशानियाँ पैदा की हैं इसके साथ ही, आयोजना भिन्न व्यय की उन मदों को खोज निकालने के लिए जोरदार प्रयत्न किए जाएंगे जिनमें कफायत की जा सकती हों।

33. वर्तमान संकेतों के आधार पर यह आशा की जा सकती है कि अगले वर्ष के राजस्व खाने में 114 करोड़ रुपये का अधिशेष (सरप्लस) रहेगा। कोई अनिश्चित कर लगाए बिना ही हम अगले वर्ष राजस्व अधिशेष की आशा करने हैं; यह तथ्य यह सूचित करता है कि पिछले वर्ष के बजट में कर के आधार को विस्तृत करने का जो प्रयत्न किया गया था उसमें बहुत सफलता मिली है। किन्तु अभी तो कहानी का एक ही भाग पूरा हुआ है। पूँजीबाते में 354 करोड़ रुपये का घाटा रहने की सम्भावना है। इस प्रकार अन्तर्निर्मित बजट में कुल मिलाकर 240 करोड़ रुपये का घाटा रहने का अनुमान है जो लगभग उतना ही है जितना चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों में दिखाया गया है। चूँकि मई मास में प्रस्तुत किए जाने वाले बजट में आयोजना परिव्यय के लिए पहले से काफी अधिक व्यवस्था करनी होगी और बजट घाटे की मात्रा को बढ़ाना भी बुद्धिमत्ता पूर्ण नहीं होगा, इसलिए साधनों के आधार को चौड़ा और गहरा करने का काम जारी रखना पड़ेगा। यदि विकास की गति को तीव्र करना है और फिर उस तीव्रता को आगे भी बनाए रखना है, तो फिर हम इस दायित्व से विनकुल नहीं बच सकते।

34. महोदय, मैंने अन्तर्निर्मित बजट की जो संक्षिप्त रूपरेखा अभी प्रस्तुत की है, वह केवल हमारे इस मंश का प्रतीक मात्र है कि हम विकास की गति को तीव्र करेंगे और समाज के कमजोर वर्गों की

आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। यदि इस बजट में आयोजना परिव्यय में वृद्धि करने और हम प्रयोजन के लिए अपेक्षित साधनों को इस तरीके से कि जिससे हमारे बड़े सामाजिक उद्देश्य भी साथ ही पूरे हो जाएं, बढ़ाने के हमारे इरादे का अधिक स्पष्ट संकेत देना सम्भव नहीं हो पाया है तो सम्मान्य सदस्य यह महसूस करेंगे कि मैं जिस बजट को प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसमें सभी वित्त मंत्रियों को सुलभ होने वाले मुख्याधार का, अर्थात् अधिक राजस्व जुटाने और राजस्व पद्धति में समुचित परिवर्तन करके आय और धन का फिर से वितरण करने की शक्ति का सहारा नहीं लिया गया है। मैं आशा करता हूँ कि मुझे आगामी सप्ताहों में सभी सम्मान्य सदस्यों से और जन साधारण से भी रचनात्मक सुझाव प्राप्त होंगे।

35. राजनीतिक स्वतंत्रता जो हमने लड़कर प्राप्त की है और लोकतंत्रीय पद्धतियाँ जो हमने स्वयं अपनाई हैं, उनमें जीवन शक्ति है, इसका जितना प्रमाण पिछले सप्ताहों में मिला है उतना पहले कभी नहीं मिला था। अब हम गरीबी और अन्याय के विरुद्ध एक नई लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे कोई संदेह नहीं कि भारत की जनता एक बार फिर विजयी होगी और इस महान और पुरातन देश में शीघ्र ही सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता का नया अरुणोदय होगा।

महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं इस सदन को यह अन्तरिम बजट समर्पित करता हूँ ।

Budget 1971-72

Speech of

Minister of Finance

24th March, 1971

Sir,

I rise to present the interim Budget for the year 1971-72. The people of India through their representatives in this Honourable House have reposed their overwhelming confidence in the Government led by Shrimati Indira Gandhi. Those of us who are privileged to belong to this Government and the Party it represents know well that we shall vindicate the verdict of the people only to the extent that we redeem our promise to promote the well-being of the poor and the unemployed in this land.

Introductory

2. Economic policies in the country have already been given a new and bold orientation towards growth with social justice in the recent past. Our task now is to reassess the entire range of our policies so as to give them a sharp focus of effectiveness, to translate these policies into concrete programmes of action and to implement these programmes with speed and determination. Only so can we accelerate the process of growth, reduce disparities in income, wealth and economic power, generate employment on a massive scale and avoid pressures on prices or balance of payments of the kind which generate internal tensions and increase our dependence on external credits.

3. The Budget of the Central Government is a powerful instrument for achieving our basic objectives. Within the few days that the new Government has been in power, it has obviously not been possible to subject our budgetary position and policies to a searching and comprehensive review. We propose, therefore, to present the Budget proper for 1971-72 in the next session of the Parliament so that Government and the Honourable Members have adequate time to review and assess the full implications of what is required at this crucial juncture in our economic history.

4. My purpose today is a limited one, *viz.*, to propose a vote on account which can be passed before the 31st March so that Government can carry on its business during the early months of the next financial year. The Finance Bill I shall introduce later today contains no new tax proposals.

5. On the expenditure side, we have taken care to provide for Defence, normal administration, assistance to the States and the Central Plan on a scale which would permit all necessary and worthwhile activities to go forward during the initial period of the vote on account. Even at this stage we propose to provide for some new and significant initiatives such as a country-wide programme of employment-oriented productive works so that their implementation can begin in right earnest. Before the presentation of the Budget proper next May, we shall review the entire position, including the scope for additional mobilisation of resources, with a view to provide for a sizeable increase in outlays on development and social welfare. The estimates of Plan expenditure, which I shall be presenting today, are tentative; and it will be our endeavour to ensure that the momentum of planned development is accelerated significantly from year to year.

Economic conditions

6. Economic conditions in the country have been, on the whole, favourable during the past 12 months. A detailed survey of the economic situation will be presented to the next session of the Parliament. Honourable Members would, however, permit me to outline briefly the strength and the weaknesses of the Indian economy during the past year.

7. For the second year in succession, the over-all rate of growth of the economy is expected to measure up fully to the targets set in the Fourth Plan. National income in real terms which had increased by about 5.5 per cent in 1969-70 is expected to register a further increase of a similar order in 1970-71.

Agriculture

8. Agricultural growth has been an important contributory factor to the over-all growth of the economy. The production of foodgrains which had recorded an increase of 5.8 per cent to 99.5 million tonnes in 1969-70 is expected to increase by another 5.5 per cent to 105 million tonnes in 1970-71. Despite progressive decline in imports, it has been possible to build up a sizeable stock of foodgrains in the hands of the Government which at present amounts to more than 5½ million tonnes as compared to less than 4½ million tonnes a year ago. The larger availability of foodgrains has also been reflected in a reduction in foodgrains prices.

9. With the exception of sugarcane, however, the production of commercial crops, notably cotton and oilseeds, has been inadequate; and this has had adverse effect on industrial production and prices. We have attempted to restrain the resultant increase in prices of major agricultural raw materials by restraint on credit and speculative activity and by larger imports. Our agricultural scientists have achieved some success in evolving new programmes for raising the productivity per hectare of commercial crops. It is necessary to extend this process not only for price stability and reduction in the reliance on imports but also for improving living conditions for most of our poorer farmers in dry areas. I can assure Honourable Members that all promising programmes for increasing yields per hectare in respect of commercial crops will receive our maximum support, both financial and otherwise.

Industry

10. During the year as a whole, industrial production is expected to increase by roughly 6 per cent. The improvement in performance has been shared not only by capital goods industries, particularly machinery and machine tools, but also by important intermediate goods industries such as aluminium, nitrogenous fertilizers, petroleum products and heavy chemicals and by a wide range of consumer goods industries. The performance of new industries and the small-scale sector has also been encouraging. Nevertheless, the fact remains that the tempo of industrial production in the country needs to be substantially accelerated and to this end the supply of both agricultural and industrial raw materials particularly steel needs to be rapidly increased. It is with this end in view that Government proposes to speed up the completion of the Bokaro Steel plant, to improve the performance of existing steel plants both in the public and the private sector and to set up three new steel plants in the southern States. Preparatory work on these new steel plants is proceeding satisfactorily. Here again, we shall not allow their progress to falter as a result of financial constraints.

11. New industrial investment propositions approved during 1970 have been much larger in magnitude than during the corresponding period in the preceding year. Production of capital goods within the country is increasing and so are the applications for the import of capital goods. We shall endeavour to accelerate this process of industrial investment so that more employment opportunities are created and there is no shortage in the coming years of key commodities.

12. Honourable Members are aware that during the last year we have taken a number of important policy decisions regarding industrial licensing, control of monopolies and greater emphasis in the policies of the public financial institutions towards assisting the backward regions and the newer entrepreneurs and towards participation in the management and the profitability of the larger units they might assist in the national interest. The vast potential for further industrial growth which has been created by our efforts over the past two decades cannot be exploited fully without bringing in a larger number of smaller people within the net-work of initiative and enterprise. When large new investments or expansion of existing large units become necessary in the over-all interests of the economy, it shall be our endeavour to reconcile growth and efficiency with reduction in the concentration of economic power by an imaginative and flexible use of the concept of the joint sector and by the expansion of the public sector.

Prices

13. In the latter part of 1970, the price situation in the country became a matter of concern as the wholesale price index from week to week remained higher by as much as 7 per cent or more when compared to the corresponding week in the preceding year. During recent weeks the general price index has shown an increase of 4 per cent or less as compared to the corresponding weeks in 1970. Even so, the price situation warrants continued vigilance and we propose to take vigorous measures to ensure a reasonable degree of stability in the prices of essential goods which enter into mass consumption.

14. The phenomenon of rising prices has been a matter of concern all over the world and there is hardly any country which has been able to avoid at least a moderate increase in prices of 3 to 4 per cent per annum in recent years. We cannot, however, ignore the implications of an unabated price increase, particularly its effects on the standard of living of the fixed income groups and the weaker sections. It is now generally recognised everywhere that without an active policy of restraint on wages and prices and, therefore, on incomes, we cannot avoid a price spiral which moves continually upwards from one industry to the other. In our circumstances, the shortage of some key raw materials which we can relieve only to a limited extent by larger imports has also been a major contributory factor. Efforts to increase production in key areas is thus an essential part of any price policy. Any attempt to accentuate unavoidable shortages in the short run by speculative activity will also have to be resisted firmly.

15. The overall growth in money supply has also been larger than what is warranted by the growth in production. The budgetary deficit at the Centre has been of the same order as set in the last Budget. However, commercial banks' borrowing from the Reserve Bank remained at unusually high levels for most part of the current year. It was against this background that the Reserve Bank raised the Bank Rate from 5 to 6 per cent early in January and took simultaneously a number of measures to encourage savings and assist deposit mobilisation and to discourage bank borrowing from the Reserve Bank except for priority purposes. These measures together with the tightening of selective controls on advances against commodities in short supply have already had a salutary effect.

Financial Institutions

16. Honourable Members would be happy to know that an impressive beginning has been made with the achievement of the objectives that we had in mind when we took the eventful step of nationalising fourteen major banks in the country. For example, in the first seventeen or eighteen months of nationalisation, i.e., between July 19, 1969 and end of December 1970, the public sector banks, i.e., the fourteen nationalised banks and the State Bank of India and its seven subsidiaries, opened, on an average, as many as 145 new branches per month as against 80 per month during the first six months of 1969 and 47 per month during 1968. Roughly 70 per cent of these new branches have been located in centres which had no banking facilities at all so far, the bulk of them being in the rural areas. The Lead Bank Scheme for the intensive development of banking in over 330 districts of the country is making satisfactory progress. Survey reports on about 80 districts have already been prepared and many more are nearing completion. The results of the surveys are being pooled and centres for new branches are being allotted continuously to the commercial banks. The record of the new branches opened in mobilising local deposits and in utilising them for productive purposes in the same areas has been particularly commendable.

17. The shift in emphasis in the matter of giving credit in favour of relatively weaker sections of the society which had hitherto been neglected by the banking system has been equally pronounced. Between June 1969 and November 1970, the aggregate number of borrowal accounts in respect of previously neglected sectors such as agriculture, small-scale industries, road transport operators, small traders and self-employed persons and professionals increased from a little less than 3 lakhs to more than 11 lakhs and the total assistance given to these sectors almost doubled. This process will gather further momentum with the formation of the Credit Guarantee Corporation of India Ltd., early this year. Small borrowers are also likely to benefit once the scheme of differential lending rates, the details of which are currently being worked out by a Committee, is introduced.

18. Honourable Members would appreciate that the ability of the public sector banks to fulfil their obligations to the weaker sections of the community without neglecting the genuine requirements of all productive establishments would depend ultimately on the success in mobilisation of deposits and on the ability to scrutinise the end-use of credit so as to eliminate all wasteful and unproductive borrowings. While the nationalised banks have made a good beginning in regard to both these objectives, I am deeply conscious of the fact that much remains to be done in this regard as also in respect of improvement of service to customers. We propose to increase greatly the facilities for meaningful training of employees and so to shape personnel policies as to bring about a greater sense of dedication and harmony among management and staff at all levels. The bank employees have been among the staunchest supporters of bank nationalisation for many years and we, on our part, have not been slow in responding to their legitimate demands for improvement in emoluments and working conditions. I hope and trust that individually as well as collectively bank employees will play their part in the vital task of economic regeneration of the country.

19. The long-term financial institutions including the Industrial Development Bank of India, Industrial Credit and Investment Corporation of India, Industrial Finance Corporation, the Life Insurance Corporation and the Unit Trust of India have had another successful year. Honourable Members are perhaps aware that a new Industrial Reconstruction Corporation with headquarters at Calcutta is being set up. This Corporation is expected to play a significant part particularly in the Eastern region in and around Calcutta. Wherever possible, the Corporation will endeavour to rehabilitate industrial units which have recently closed down or are facing the risk of closing down by reconstruction of the share capital, strengthening of management, diversification of products, improvement in technology and labour relations and provision of finance on suitable soft terms. I have no doubt that with the active cooperation and participation of all concerned this Corporation will play a useful role in reducing unemployment as well as economic and social tensions in a vital area of the economy.

Balance of Payments

20. Honourable Members would be happy to know that by the end of the current fiscal year, we would have repaid all the outstanding drawings on the International Monetary Fund that we had to make during the critical years of 1966 and 1967. In addition, we have fulfilled our obligations in relation to an increase in our International Monetary Fund quota from 750 million to 940 million dollars. We have also been an important beneficiary of the scheme for the creation of Special Drawing Rights.

21. While the overall improvement in our foreign exchange position during the past two or three years has been unmistakable, I cannot help emphasising that there is no room for complacency whatsoever in regard to our balance of payments. During the current fiscal year, for example, the improvement in our position vis-a-vis the International Monetary Fund will be matched by a corresponding decline in our own reserves including Special Drawing Rights so that, on balance, our total reserves position will show little or no improvement. There has also been a substantial increase in import licences issued for the maintenance of the economy the full impact of which is yet to be felt. Much greater and continuing effort on a wide front would also be necessary if the target of a 7 per cent per annum increase in export earnings set in the Fourth Plan is to be realised from year to year. The outlook regarding the net inflow of foreign aid remains uncertain. This is particularly so in respect of readily useable aid such as non-project assistance and refinancing of our heavy debt repayments.

22. Against this background, it would be prudent on our part to seize every worthwhile opportunity for export promotion as well as import substitution and to exercise the maximum restraint on the imports and consumption of less essential items. This underlines once more the need for keeping a firm rein over costs and prices, and for the deployment of fiscal instruments to regulate consumption. The priorities in investment also have to be guided by the exigencies of the balance of payments. Let us not forget that our objective is to combine growth not only with social justice but also with self-reliance. We have a long way to go before we can rest content with our achievement on any one of these fronts.

Employment

23. By far the most urgent problem that needs our whole-hearted attention is the problem of unemployment. It is this more than anything else which poses a threat to the stability of our young democracy. There are indications that the employment situation in the country has improved somewhat in response to the revival of agricultural and industrial production over the past two years. But the fact remains that notwithstanding the rapid economic strides we have taken over the past two decades, the twin problems of mass poverty and unemployment remain as acute as ever. In large pockets, there has perhaps been a worsening of conditions. There can be no question that poverty and unemployment cannot be eradicated without a sustained process of growth. But there are several ways of achieving growth, and we have to seek out those which make the maximum impact on unemployment and mass poverty.

24. It was with this end in view that the Government took a decision some time back that new employment-oriented schemes should be taken up in each district in the country with a view to provide employment to at least one person in every family. Instructions have already gone to the State Governments to prepare schemes which apart from creating additional employment opportunities would also add to the productive potential in each district. In the Budget for 1971-72 a provision of Rs. 50 crores is being made to support this country-wide programme of creating more employment opportunities with a productive bias.

25. The Committee which was set up by the Reserve Bank of India to review the special credit schemes of the commercial banks has offered a number of valuable suggestions for promoting and encouraging self-employment. The recommendations made by the Committee are receiving urgent attention and decisions thereon will be taken expeditiously.

Budgetary Out-turn 1970-71

26. The Budget introduced last year by the Prime Minister provided for a substantial increase in Plan outlay at the Centre, massive assistance to the States for a similar increase in Plan outlay at the State level and a series of new initiatives in order to combine growth with a greater regard for the welfare of the most needy sections of society. During the year, we have honoured our commitments to the States and have indeed given substantial assistance in addition to what was provided in the Budget for urgently felt needs such as those for the improvement of living conditions in the Calcutta Metropolitan Area and for relief in the flood and famine-stricken areas in other States. The minimum pension as also family pension for Central Government employees has already been increased. A similar scheme for family pensions as well as lump sum payment in the event of death has already been introduced in respect of industrial workers who are liable to pay contribution to the Employees Provident Fund at the rate of 6½ per cent of their pay as well as for workers covered by the Coal Mines Provident Fund and Bonus Scheme Act, 1948. The newly set up Housing and Urban Development Finance Corporation has made a beginning with its activities and it shall be our endeavour to ensure that these activities gather rapid momentum so that there is visible improvement in some of our largest urban conglomerations. The nutritional programmes for children in tribal blocks and slum areas, extension of drinking water and special schemes for small farmers, marginal farmers and dry farming areas have been taken in hand. While the expenditure on selective rural works programmes in chronically drought affected areas is likely to fall short of the target of Rs. 25 crores because of the time taken in preparing and finalising worthwhile schemes, Honourable Members would note that outside this provision a sum of Rs. 100 crores has been provided for natural calamities relief as against the Budget provision of Rs. 50 crores only. Provision is being made in the Budget for the coming year for the continuation of these special schemes.

27. There is every reason to believe that the step-up in Plan outlay envisaged at the State level during the current year will be achieved and in fact in several States Plan outlay will exceed the initial provision. The provision for special assistance to the States in a weaker financial position has been increased from Rs. 175 crores provided in the Budget to Rs. 195 crores which is being provided in the Revised Estimates. It is, however, a matter of some concern that despite the enlarged provision for special accommodation, a number of State Governments have continued to incur large overdrafts with the Reserve Bank of India, thus adding to inflationary pressures in the economy. Considering the fact that funds to be earmarked for special accommodation are going to be smaller in the coming years as

per the agreed pattern, it is vitally important that State Governments, no less than the Centre, observe the strictest fiscal discipline and adopt all possible measures to raise and conserve resources.

28. As far as the Centres Plan outlay is concerned, indications are that the actual expenditure in 1970-71 would show a substantial increase of the order of Rs. 180 crores over the actual expenditure in 1969-70. It is a matter of great disappointment, however, that the actual outlay in both the years is likely to show a significant shortfall in relation to the original Budget provisions. Many of the industrial projects in the Central sector, notably Bokaro Steel Plant, the Refractory plants and petro-chemical projects have not been able to get into stride as rapidly as was expected. Clearly, we need to examine critically our present procedures for the scrutiny and sanctioning of major Plan schemes and to put greater speed in implementation. We propose to review the progress of major schemes included in the Central Plan so that the provision made for them in the coming year is as realistic as possible. Additional schemes, particularly those which can be taken up quickly and which can yield quick returns and make an impression at the same time on the well-being of the poorer sections of the community will also be kept ready to make up for shortfalls which become inevitable. I would like to make it absolutely clear to Honourable Members that while some re-adjustment of Plan priorities and re-arrangement of Plan programmes are obviously called for, there is no question whatsoever of reducing the size of the Plan. Quite the contrary is our intention.

29. In the Revised Estimates for the current financial year, tax revenue—particularly revenues, under Income and Corporate Tax—are expected to show some improvement over the Budget Estimate for 1970-71. The Revised Estimates for the current year thus show a tax revenue of Rs. 3,198 crores against the Budget Estimates of Rs. 3,134 crores. There is likely to be a similar increase in non-tax revenue as well. This improvement under revenue receipts, however, will be offset by a reduction of about Rs. 26 crores under market loans and of nearly Rs. 50 crores under external assistance. I have already referred, briefly, to the position regarding expenditure in the current year on the Plan and by way of assistance to the States. On non-Plan expenditure, a major item of variation has been the incidence of the interim award of the Pay Commission which was accepted in toto by the Government. On the whole, and in part as a result of the incidence of the Pay Commission's interim award, the contribution of Public Sector enterprises to the Budget is expected to be of a lower order. Loans to some of these enterprises for meeting their cash loss and working expenses would also be some Rs. 30 crores larger than what was provided in the Budget. On balance, the budgetary deficit at the Centre in the Revised Estimates for the current year is now estimated at Rs. 210 crores, i.e., roughly of the same order as the Budget Estimate of Rs. 227 crores.

Budget Estimates, 1971-72

30. At existing rates of taxation, total tax revenue next year is estimated at Rs. 3,403 crores, of which the share of the States will be Rs. 850 crores. Non-tax revenue excluding food aid and PL 480 revenue grants is expected to increase from Rs. 903 crores this year to Rs. 966 crores next year. While receipts under market loans and small savings will show an increase, receipts under external assistance are expected to show a significant decline from Rs. 518 crores this year to Rs. 421 crores in 1971-72. The major part of this decline is accounted for by receipts under PL 480. Net receipts from non-project and project assistance also are likely to decline from Rs. 355 crores in the Revised Estimates this year to Rs. 224 crores next year.

31. On the expenditure side, normal administrative expenditure will show an increase of Rs. 15 crores over the current year's level. An additional provision of Rs. 65 crores is being made for expenditure on Defence both revenue and capital as compared to the Budget provision in the current year. The provision of Rs. 50 crores for employment-oriented schemes to which I have referred earlier is for the time being treated as outside the Plan. Excluding this, the provision in the Central Budget for the Plan for 1971-72 will be Rs. 1980 crores representing an increase of Rs. 74 crores over the Budget Estimates for the current year. This entire increase is by way of Plan assistance to the State Governments and the Union Territories, the provision for which is being increased from Rs. 711 crores in the current year to Rs. 785 crores in the coming year. This is in accordance with the discussions held between the Planning Commission and the State Governments regarding their Plans for 1971-72. I have chosen to make full provision for Plan assistance to the States

per the agreed pattern, it is vitally important that State Governments, no less than the Centr., observe the strictest fiscal discipline and adopt all possible measures to raise and conserve resources.

28. As far as the Centres Plan outlay is concerned, indications are that the actual expenditure in 1970-71 would show a substantial increase of the order of Rs. 180 crores over the actual expenditure in 1969-70. It is a matter of great disappointment, however, that the actual outlay in both the years is likely to show a significant shortfall in relation to the original Budget provisions. Many of the industrial projects in the Central sector, notably Bokaro Steel Plant, the fertilizer plants and petro-chemical projects have not been able to get into stride as rapidly as was expected. Clearly, we need to examine critically our present procedures for the scrutiny and sanctioning of major Plan schemes and to put greater speed in implementation. We propose to review the progress of major schemes included in the Central Plan so that the provision made for them in the coming year is as realistic as possible. Additional schemes particularly those which can be taken up quickly and which can yield quick returns and make a contribution to the same time on the well-being of the poorer sections of the country will be kept ready to make up for shortfalls which become inevitable. It is absolutely clear to Honourable Members that while the re-arrangement of Plan priorities and re-arrangement of Plan programmes are being carried out, there is no question whatsoever of reducing the size of the Plan. Quite the contrary is our intention.

29. In the Revised Estimates for the current financial year, tax revenues—particularly revenues, under Income and Corporate Tax—are expected to show some improvement over the Budget Estimate for 1970-71. The Revised Estimates for the current year thus show a tax revenue of Rs. 3,198 crores against the Budget Estimates of Rs. 3,134 crores. There is likely to be a similar increase in non-tax revenue as well. This improvement under revenue receipts, however, will be offset by a reduction of about Rs. 26 crores under market loans and of nearly Rs. 50 crores under external assistance. I have already referred, briefly, to the position regarding expenditure in the current year on the Plan and by way of assistance to the States. On non-Plan expenditure, a major item of variation has been the incidence of the interim award of the Pay Commission which was accepted in toto by the Government. On the whole, and in part as a result of the incidence of the Pay Commission's interim award the contribution of Public Sector enterprises to the Budget is expected to be of a lower order. Loans to some of these enterprises for meeting their cash loss and working expenses would also be some Rs. 30 crores larger than what was provided in the Budget. On balance, the budgetary deficit at the Centre in the Revised Estimates for the current year is now estimated at Rs. 230 crores, i.e. roughly of the same order as the Budget Estimate of Rs. 227 crores.

Budget Estimates, 1971-72

30. At existing rates of taxation, total tax revenue next year is estimated at Rs. 3,403 crores, of which the share of the States will be Rs. 350 crores. Non-tax revenue excluding food aid and PL 480 revenue grants is expected to increase from Rs. 993 crores this year to Rs. 966 crores next year. While receipts under market loans and small savings will show an increase, receipts under external assistance are expected to show a significant decline from Rs. 518 crores this year to Rs. 421 crores in 1971-72. The major part of this decline is accounted for by receipts under PL 480. Net receipts from non-project and project assistance also are likely to decline from Rs. 355 crores in the Revised Estimates this year to Rs. 324 crores next year.

31. On the expenditure side normal administrative expenditure will show an increase of Rs. 15 crores over the current year's level. An additional provision of Rs. 65 crores is being made for expenditure on Defence both revenue and capital as compared to the Budget provision in the current year. The provision of Rs. 50 crores for employment-oriented schemes to which I have referred earlier is for the time being treated as outside the Plan. Excluding this, the provision in the Central Budget for the Plan for 1971-72 will be Rs. 1980 crores representing an increase of Rs. 74 crores over the Budget Estimates for the current year. This entire increase is by way of Plan assistance to the State Governments and the Union Territories, the provision for which is being increased from Rs. 711 crores in the current year to Rs. 785 crores in the coming year. This is in accordance with the discussions held between the Planning Commission and the State Governments regarding their Plans for 1971-72. I have chosen to make full provision for Plan assistance to the States